Part XIII: Trade and Commerce within the territory of India

Part XIII of the Constitution of India deals with Trade and Commerce within the territory of India. It contains provisions regarding the regulation of trade and commerce within the territory of India, the power of the Union to regulate inter-State trade and commerce, and the protection of the interests of the consumers.

Article 301 provides for the freedom of trade, commerce, and intercourse throughout the territory of India, and lays down the provisions regarding the restriction of such freedom by the Union or the States.

Article 302 allows Parliament to impose restrictions on the freedom of trade, commerce, and intercourse in public interest, and lays down the provisions regarding the nature of such restrictions.

Article 303 provides for the power of Parliament to give precedence to the laws made by Parliament over the laws made by the States with respect to trade and commerce.

Article 304 allows the States to impose restrictions on the freedom of trade, commerce, and intercourse, but lays down the provisions regarding the nature of such restrictions and the conditions under which they can be imposed.

Article 305 provides for the saving of the existing laws relating to trade and commerce, and lays down the provisions regarding the continuance of such laws until they are amended or repealed by the Union or the States.

Article 307 provides for the power of the President to declare an emergency in case of a substantial reduction in the supplies of certain essential commodities, and lays down the provisions regarding the powers of the Union and the States during such emergency.

Overall, Part XIII of the Constitution of India lays down the provisions regarding the regulation of trade and commerce within the territory of India, the power of the Union to regulate inter-State trade and commerce, and the protection of the interests of the consumers, and aims to ensure the smooth functioning of the trade and commerce system in India.

भाग XIII: भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य

भारत के संविधान का भाग XIII भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के नियमन, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने की संघ की शक्ति और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 301 भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और संघ या राज्यों द्वारा ऐसी स्वतंत्रता के प्रतिबंध के संबंध में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 302 संसद को सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, और ऐसे प्रतिबंधों की प्रकृति के संबंध में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को प्राथमिकता देने के लिए संसद की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 304 राज्यों को व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों की प्रकृति और उन शर्तों के बारे में प्रावधान करता है जिनके तहत उन्हें लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 305 व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मौजूदा कानूनों को बचाने के लिए प्रदान करता है, और ऐसे कानूनों की निरंतरता के संबंध में प्रावधान करता है जब तक कि उन्हें संघ या राज्यों द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 307 कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में पर्याप्त कमी के मामले में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, और ऐसे आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों की शक्तियों के संबंध में प्रावधान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग XIII भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के नियमन, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए संघ की शक्ति, और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के बारे में प्रावधान करता है, और इसका उद्देश्य भारत में व्यापार और वाणिज्य प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है।